

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जून 2024 — आषाढ़ 3, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 जून 2024

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-6/2024/एक/6.— इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/ 2019/एक/6, दिनांक 27 फरवरी, 2019 द्वारा “मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” का गठन किया गया था। उक्त आदेश को अधिकृत करते हुए राज्य शासन एतद्वारा “मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” को निम्नानुसार पुनर्गठित करता है :-

#### 1— प्राधिकरण के उद्देश्य—

- (1) बस्तर तथा सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित जिलों के अतिरिक्त शेष आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
- (2) प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवैधानिक संरक्षण हेतु उपाय सुझाना।
- (3) राज्य शासन की जनजाति विकास से संबंधित नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देना।
- (4) प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति समुदायों की आवश्यकताओं को पहचान कर, राज्य के विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित करवाने की पहल करना।
- (5) क्षेत्रीय विकास के लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप छोटे-छोटे विकास कार्यों की त्वरित स्वीकृति प्रदान करना।

#### 2— प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र—

प्राधिकरण के क्षेत्र में सम्पूर्ण राजस्व जिला कोरबा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के अतिरिक्त कमशः जिला गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बालोद, राजनांदगांव, खेरागढ़-छुईखदान-गण्डई, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सकती के आंशिक क्षेत्र जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (यथा-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र, माडा पॉकेट, लघु अंचल) में सम्मिलित है। सूची परिशिष्ट-‘अ’ में दर्शित है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/बस्तियों के मजरा, टोला, पारा, मोहल्ला एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थित पारा-मोहल्ला जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हों सम्मिलित होंगे।

#### 3— प्राधिकरण का गठन—

प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार होगा—

1—	माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2—	क्षेत्र के निर्वाचित माननीय विधायक (अ.ज.जा आरक्षित)	उपाध्यक्ष
3—	माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग	सदस्य
4—	माननीय मंत्री, वित्त विभाग	सदस्य
5—	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र—	सदस्य
15	लैलूंगा	18 खरसियां
20	रामपुर	21 कोरबा
23	पाली—तानाखार	22 कटघोरा
56	सिहावा	55 बिन्द्रानवागढ़
	60 डौंडीलोहारा	78 मानपुर—मोहला
6—	आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम 02 समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7—	मुख्य सचिव	सदस्य
8—	सचिव, आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग	सदस्य
9—	मान.मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य—सचिव

प्राधिकरण अपनी बैठकों में नियमित रूप से या विशेष रूप से किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा।

#### 4— प्राधिकरण की बैठक—

प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक छैमाही में पूर्व निर्धारित तिथि पर होगी। बैठक स्थल, दिन, समय एवं चर्चा के बिन्दुओं (एजेण्डा) की संसूचना प्राधिकरण के समस्त सदस्यों को बैठक की तिथि से कम से कम सात दिवस पूर्व दी जावेगी। बैठक में लिए गए निर्णयों/संस्तुतियों से सभी सदस्यों को बैठक की कार्यवाही विवरण के माध्यम से अवगत कराया जावेगा।

#### 5— प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियाँ—

- (1) प्राधिकरण, क्षेत्र के विकास की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पहल करना तथा राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
- (2) प्राधिकरण को शासकीय योजनाओं के अनुकूलतम उपयोग के लिए संबंधित विकास विभाग को दिशा—निर्देश/मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा।
- (3) अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक हितों के संरक्षण के लिए प्रचलित शासकीय नीतियों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश/मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा।
- (4) प्राधिकरण को राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई अनाबद्ध राशि (अन्टाईट फण्ड) से क्षेत्र के लिए नितांत आवश्यक स्थानीय महत्व के छोटे—छोटे विकास कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा।
- (5) प्राधिकरण क्षेत्र में कार्यरत समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व शासन से सहायता प्राप्त निगमों, मण्डलों, संघों, प्राधिकरणों के पदाधिकारियों की बैठक आहूत कर उनके कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकेगा अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से करवा सकेगा। प्राधिकरण इन संस्थाओं को अपने सुझावों/संस्तुतियों से अवगत करा सकेगा।
- (6) अन्य ऐसे समस्त विधिक कार्य संपादित करने की शक्ति होगी, जो प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों।

#### 6— प्राधिकरण के निर्णयों एवं वित्तीय स्वीकृतियों का क्रियान्वयन—

प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णयों, वित्तीय स्वीकृतियों की संसूचना माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पश्चात् प्राधिकरण के सदस्य—सचिव के हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

**7— प्राधिकरण की निधि का नियम—**

- (1) प्राधिकरण निधि का उपयोग प्राधिकरण के निधि नियम के अनुरूप किया जाएगा।
- (2) राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण को आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग के बजट में मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष-4225 व 2225, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण-7995, 11112 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, #45-पूँजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं #14-सहायक अनुदान के अंतर्गत प्रतिवर्ष रुपये 50 करोड़ या माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देशानुसार इससे अधिक विकल्प राशि उपलब्ध कराई जावेगी।
- (3) प्राधिकरण के अध्यक्ष को, प्राधिकरण की निधि से क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा। विकास कार्यों की स्वीकृतियाँ प्राधिकरण के माननीय सदस्यों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं की तात्कालिक मांग को दृष्टिगत रखते हुए दी जाएगी।
- (5) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के भुगतान तथा सामान्य प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापना अनुदान में रुपये 50.00 लाख का प्रावधान होगा।
- (6) प्राधिकरण से स्वीकृत राशि का लेखा परीक्षण जिला स्तर पर विभागीय बजट से पुनराबंटित राशि की प्रकिया तथा कोष एवं लेखा के निर्देशों के अनुरूप महालेखाकार, छत्तीसगढ़ से कराया जाएगा। मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा कोष एवं लेखा के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

**8— प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को सुविधाएं—**

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निजी कार्यालय के लिए स्टाफ की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं के अनुरूप होगी। यह सुविधाएं प्रशासकीय विभाग (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) द्वारा की जाएगी।

**9— प्राधिकरण प्रकोष्ठ—**

प्राधिकरण से संबंधित समस्त मंत्रालयीन कार्यों के निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में एक "प्रकोष्ठ" का गठन किया जावेगा। "प्रकोष्ठ" में एक प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयीन स्टाफ होगा। इन कर्मचारियों के वेतन, भत्तों की व्यवस्था संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण प्रकोष्ठ का दायित्व होगा कि—

- 1— प्राधिकरण की बैठकों की संसूचना जारी करना।
- 2— प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्रवाई विवरण तैयार करना तथा माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पश्चात् यह कार्रवाई विवरण सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।
- 3— संबंधित विभाग/एजेंसियों से कार्रवाई विवरण के अनुसार प्राधिकरण के निर्णयों का पालन सुनिश्चित करवाकर पालन प्रतिवेदन प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करना।
- 4— प्राधिकरण की निधि से स्वीकृत हुए कार्यों की कार्य स्वीकृति आदेश सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के लिए जारी करना।
- 5— प्राधिकरण की स्वीकृतियों की जानकारी अद्यतन रखना तथा आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा दी गई पुनराबंटन स्वीकृतियों का मिलान कर यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण से कार्य स्वीकृति पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा पुनराबंटन स्वीकृति जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि कोष एवं लेखा के निर्देशों के अनुरूप लेखा का संधारण प्रशासकीय विभाग आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा ही किया जाएगा।
- 6— यह सुनिश्चित करना कि आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा दी गई पुनराबंटन स्वीकृति पश्चात् संबंधित विभाग/जिला कलेक्टर्स के द्वारा एक माह की समयावधि में वित्त विभाग एवं भंडार कय नियमों का पालन करत हुए कार्य प्रारंभ कर दिया जाए।
- 7— प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, संबंधित विभाग/जिला कलेक्टर्स से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त कर प्रगति की जानकारी, सदस्य सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना।
- 8— माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव, प्राधिकरण के निर्देशानुसार समस्त दायित्वों का निर्वहन करना।

हस्ता./—

(डी.डी. सिंह)

सचिव.

## छ.ग. राज्य मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्र

संभाग	जिला	सम्मिलित क्षेत्र (विकासखण्ड/गांव)	उपयोजना क्षेत्र का विवरण
रायपुर	गरियाबंद	वि०खं० गरियाबंद, छुरा, मैनपुर (सम्पूर्ण)	एकी.आ.परि. गरियाबंद
	धमतरी	वि०खं० नगरी (सम्पूर्ण) वि०खं० मगरलोड के 49 गांव.	एकी.आ.परि. नगरी
		वि०खं० धमतरी के 43 गांव.	(माडा पाकेट गंगरेल)
	महासमुन्द	वि०खं० महासमुन्द-74 गांव , वि०खं० बागबाहरा-85 गांव. वि०खं० पिथौरा, 41 व 89 गांव वि०खं० सरायपाली-52 गांव. वि०खं० बसना-74 गांव.	(माडा पाकेट महासमुन्द-1, एवं 2)
	बलौदाबाजार- भाटापारा	वि०खं० भाटापारा-13 गांव. वि०खं० बलौदाबाजार-12 गांव. वि०खं० कसडोल के 118 गांव.	(लघु अंचल धुरीबंधा) (माडा पाकेट बलौदाबाजार)
	सारंगढ- बिलाईगढ-	वि०खं० बिलाईगढ-29 गांव. वि०खं० सारंगढ-57 गांव.	(माडा पाकेट बलौदाबाजार) (माडा पाकेट सारंगढ)
दुर्ग	बालोद	वि०खं० डौंडी(सम्पूर्ण), वि०खं० डौंडीलोहारा के 190 गांव, वि०खं० गुरुर-38 गांव. वि०खं० बालोद-29 गांव,	एकी.आ.परि. डौंडीलोहारा
	राजनांदगांव	वि०खं० छुरिया-120 गांव, वि०खं० डोंगरगांव -02 गांव, वि०खं० डोंगरगढ-47 गांव. वि०खं० डोंगरगढ-15 गांव,	एकी.आ.परि. राजनांदगांव (लघु अंचल बछेराभाटा)
	मोहला-मानपुर अम्बा चौकी	वि०खं० अम्बागढ चौकी, मानपुर, मोहला(सम्पूर्ण),	एकी.आ.परि. राजनांदगांव
	खैरागढ- छुईखदान- गण्डई	वि०खं० छुईखदान-76 गांव वि०खं० खैरागढ-1 गांव वि०खं० खैरागढ-20 गांव वि०खं० छुईखदान-15 गांव।	(माडा क्षेत्र नचनिया) (लघु अंचल बछेराभाटा)
	कबीरधाम	वि०खं० बोडला के 219 गांव। वि०खं० पंडरिया के 81 गांव।	(माडा पाकेट कबीरधाम) एकी.आ.परि. गौरेला
संभाग	जिला	सम्मिलित क्षेत्र (विकासखण्ड/गांव)	उपयोजना क्षेत्र का विवरण
बिलासपुर	बिलासपुर	वि०खं० तखतपुर- 15 गांव, वि०खं० बिल्हा-11, मस्तूरी-15, वि०खं०कोटा के 140 गांव.	एकी.आ.परि. गौरेला एकी.आ.परि. कोरबा
	गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही	वि०खं० मरवाही, गौरेला, (पेण्ड्रारोड) पेण्ड्रा (सम्पूर्ण),	एकी.आ.परि. गौरेला
	मुंगेली	वि०खं० लोरमी के 47 गांव.	
	कोरबा	सम्पूर्ण राजस्व जिला	एकी.आ.परि. कोरबा
	रायगढ	वि०खं० धरमजयगढ, लैलूंगा,घरघोड़ा, तमनार, खरसिया (सम्पूर्ण) वि०खं० बरमकेला-43 गांव. गोपालपुर-33 गांव ,	एकी.आ.परि.धरमजयगढ ( माडा पाकेट सारंगढ) ( माडा पाकेट गोपालपुर)
	सक्ती	वि०खं० सक्ती के 46 गांव.	(माडा पाकेट रूगजा)

अटल नगर, दिनांक 24 जून 2024

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-11/2024/एक/6.— इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/ 2019/एक/6, दिनांक 19 जून, 2019 द्वारा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण निधि नियम, 2019 अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :-

## 1— संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण निधि नियम, 2024 होगा।
- (2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) इसका विस्तार संबंधित प्राधिकरण की सीमा तक होगा।

## 2— परिभाषाएं—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “प्राधिकरण” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है।
- (ख) “प्ररूप” से अभिप्रेत है, वे प्रपत्र जिनमें विकास कार्यों का विवरण एवं इस पर व्यय की जाने वाली राशि आदि का अभिलेख उल्लेखित हो।
- (ग) “निधि” से अभिप्रेत है, प्राधिकरण को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के बजट से प्रतिवर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष-4225 व 2225, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण-7995, 11112 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण #45-पूँजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं #14-सहायक अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली राशि जिससे प्राधिकरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

## 3— निर्णयों का क्रियान्वयन—

- (1) प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत अधोसंरचनाओं के विकास तथा हितग्राही मूलक कार्यों के लिए माननीय सदस्य, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, संबंधित विभाग/जिला कलेक्टर के मांग-पत्र प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकरण की स्वीकृति/प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में दी जाएगी।
- (2) प्राधिकरण/प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा दी गई स्वीकृति की संसूचना सदस्य-सचिव, प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएगी। वित्तीय स्वीकृति की संसूचना आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रेषित करते हुए, संबंधित विकास विभाग/जिला कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा।
- (3) सदस्य सचिव, प्राधिकरण से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा नियत की गई निर्माण एजेंसी प्ररूप-“क” में विकास कार्यों का विवरण देते हुए, तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी।
- (4) निर्माण एजेंसी के द्वारा प्ररूप-“क” में प्रस्ताव मय आवश्यक दस्तावेज, ड्राईंग, साईट प्लान, भौतिक सीमा चिन्ह, नक्शा व खसरा (पांच साल) सहित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।
- (5) जिला कलेक्टर निर्माण एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत प्ररूप-“क” एवं संलग्न आवश्यक दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण करते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा, इसमें कार्य की सक्षमता अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति भी सम्मिलित होगी।
- (6) कलेक्टर को एक करोड़ रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार होगा, इसके ऊपर की राशि संबंधित विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
- (7) स्वीकृत कार्यों के लिए प्ररूप-“क” तथा प्रशासकीय स्वीकृतियों का संधारण जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एक सेल बनाकर करेंगे।

## 4— प्राधिकरण के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य—

- 1) आधारभूत नागरिक सुविधाओं के कार्य— सी0सी0 रोड निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल सुविधाओं का विस्तार, नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प की स्थापना, हाट-बाजार में शौचालय निर्माण, तालाब में पचरी निर्माण।

- 2) सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्य— सामुदायिक भवन निर्माण, सांस्कृतिक भवन निर्माण एवं रंगमंच/कला मंच निर्माण, चबूतरा निर्माण, मुक्तिधाम शेड निर्माण। सभी भवनों के निर्माण कार्य में विद्युत व्यवस्था अनिवार्य रहेगा।
- 3) शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में शाला भवन/छात्रावास भवन/आश्रम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पेयजल व्यवस्था, शौचालय का निर्माण, कन्या शालाओं में बाउण्ड्रीवाल/आहता निर्माण।
- 4) स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार— स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, मरीजों के परिजनों के लिए सराय निर्माण, अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था।

इत्यादि सभी कार्य जिससे प्राधिकरण क्षेत्र के विकास तथा अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति के परिरक्षण में सहायक हो लिये जा सकेंगे। ऐसे कार्य जो किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन अथवा प्रचार में सहायक होते हैं, को प्राधिकरण द्वारा प्रश्रय नहीं दिया जाएगा।

#### 5— प्राधिकरण की निधि के लिए बजट का प्रावधान—

प्राधिकरण के लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के विभागीय बजट में प्रतिवर्ष 50.00 करोड़ या इससे अधिक राशि मांग संख्या-41, 7995-मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, लेखा शीर्ष-4225, #45-पूँजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण, 001- पूँजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा लेखा शीर्ष-2225 #14-सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान अंतर्गत उपलब्ध होगी। प्राधिकरण से स्वीकृति के अनुक्रम में सदस्य सचिव, प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति पत्र आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, अटल नगर नवा रायपुर को प्रेषित किया जाएगा।

#### 6— उपाध्यक्ष कार्यालय के लिए राशि का प्रावधान—

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय की पूर्ति के लिए बजट का प्रावधान आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के बजट से किया जावेगा। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास प्रावधानित बजट संबंधित जिला कलेक्टर के विकल्प पर पुनराबंटित करेंगे।

#### 7— निधि से राशि की स्वीकृति जारी करना—

- (1) प्राधिकरण/प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्यों की वित्तीय स्वीकृति सदस्य-सचिव प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा। जिसके आधार पर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर को राशि पुनराबंटित की जावेगी।
- (2) कलेक्टर द्वारा वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप दो अथवा तीन किशतों में कार्यों की प्रगति के अनुसार राशि क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी।
- (3) कार्य की समाप्ति उपरांत कार्य का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर्स द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुत किया जावेगा। जिसका संधारण राज्य शासन एवं वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

#### 8— कार्य निरीक्षण प्रतिवेदन—

जिला कलेक्टर्स प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यों के नियमित निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन को छोड़कर अन्य विभाग के सक्षम तकनीकी अधिकारियों को शामिल कर निरीक्षण समिति गठित करेंगे। यह समिति प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यों का स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम प्रशासकीय अधिकारी के द्वारा सैम्पल निरीक्षण करवाकर अपने अभिमत सहित सदस्य सचिव, प्राधिकरण एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को त्रैमासिक प्रतिवेदन के आधार पर अवगत कराएंगे।

#### 9—पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्ति—

प्राधिकरण की निधि से स्वीकृत कार्य पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्त रहेंगे। संबंधित निर्माण विभाग एवं क्रियान्वयन एजेंसी को केवल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा में ही राशि भुगतान की जाएगी।

#### 10— लेखा संधारण की रीति—

- (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में राशि पुनराबंटन की स्वीकृति तथा व्यय की जानकारी प्राधिकरण "प्रकोष्ठ" द्वारा संधारित किया जायेगा।
- (2) निधि से पुनराबंटित राशि, व्यय एवं तत्संबंधी अन्य विषयों का लेखा/लेखा संधारण, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में इस हेतु एक प्रभारी अधिकारी को नियुक्त कर, राज्य सरकार की राशि के लेखा संधारण की भांति किया जाएगा।

**11— प्राधिकरण की निधि से तैयार आस्तियों का रख रखाव एवं संधारण—**

- (1) प्राधिकरण की निधि से निर्मित आस्तियों का लेखा-जोखा संबंधित विभाग द्वारा संधारित किया जाएगा। इन आस्तियों के उपयोग एवं रख रखाव का उत्तरदायित्व भी संबंधित विभाग का होगा। विभाग इन आस्तियों को अपने "बुक्स" में लेंगे।
- (2) प्राधिकरण निधि से निर्मित अधोसंरचना स्थल में सीमेंट की बनी पट्टिका जिसमें प्राधिकरण का नाम, स्वीकृत कार्य का विवरण, स्वीकृति वर्ष, स्वीकृत राशि इत्यादि का उल्लेख हो, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

**12— लेखाओं का पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण—**

- (1) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा लेखा विवरण का समय-समय पर पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं निरीक्षण किया अथवा करवाया जाएगा।
- (2) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं जिला कलेक्टर कार्यालयों में विकास प्राधिकरण की राशि से संपादित होने वाले कार्यों से संबंधित लेखाओं का अंकेक्षण, महालेखाकार के आडिट दल से नियमानुसार किया जाएगा।
- (3) प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों का मूल्यांकन/पर्यवेक्षण आंतरिक एवं बाह्य एजेंसी से करवाने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा।
- (4) वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यों की सूचना अध्यक्ष, प्राधिकरण द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के लिए दी जाएगी।

हस्ता./—

(डी.डी. सिंह)  
सचिव.

प्ररूप—''क''  
देखें नियम-3(4)

प्रति,  
कलेक्टर,  
जिला—.....

महोदय,

दिनांक.....को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक.....के अनुसार विकास कार्य .....को.....स्थल में निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिस हेतु .....विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है।

2. इस निर्णय के अनुसरण में कार्यस्थल का पूर्ण निरीक्षण कर कार्य के परिमाण का आंकलन विभाग द्वारा किया गया। इस आंकलन में कार्य से संबंधित तकनीकी प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य किया गया है। तकनीकी स्वीकृति क्रमांक.....दिनांक.....द्वारा सक्षम अधिकारी.....द्वारा दी गई है।

3. इस.....विकास कार्य को पूर्ण करने में राशि .....रूपये शब्दों में .....की लागत आना आंकलित है।

4. कृपया इस कार्य एवं राशि का प्रशासनिक अनुमोदन सक्षमता अनुसार जारी करने का कष्ट करें।  
संलग्न:-तकनीकी प्रतिवेदन।

क्रियान्वयन एजेंसी का नाम.....

प्रस्तावक का नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय की मुद्रा

स्थान :  
दिनांक :



प्रमाण-पत्र  
देखें नियम-3(6)

दिनांक.....को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक.....के अनुसरण में स्थल.....में विकास कार्य .....को कराये जाने की स्वीकृति दी गई है, जिस हेतु .....विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त/नियत किया गया है।

2. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्थल निरीक्षण एवं सर्वे इत्यादि कर इस विकास कार्य को संपादित करने में राशि .. रुपये (शब्दों में ..... ) की राशि का व्यय होना आंकलित किया गया है।

3. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य को पूर्ण करने में .....अवधि लगने की संभावना व्यक्त की गई है।

4. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्ररूप-क में कार्य की सक्षम तकनीकी स्वीकृति की सूचना दी गई है। कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी .....द्वारा क्रमांक..... दिनांक .....द्वारा दी गई है।

5. इस विकास कार्य पर लगने वाली आंकलित राशि की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति भी ले ली गई है। प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी .....के क्रमांक ..... दिनांक .....द्वारा दी गई है।  
संलग्न:-प्ररूप-क।

कलेक्टर  
जिला-.....

स्थान :  
दिनांक :